



राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

प्रलिस के ललल:

मानव तसकरी, जाली मुद्रा या बैंक नोट, साइबर-आतंकवाद, NIA, सूचीबद्ध अपराध, आतंकवाद, LWE, उग्रवाद, कट्टरता, NIA अधनललम 2008

मेन्स के ललल:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका कार्य और क्षेत्राधिकार, कट्टरता- मुद्रा, चुनौतललल, समाधान ।

चर्चा में क्यूल?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA)** ने दो लूलुु के खललल एक **प्राथमकी/प्रथम सूचना रललरट** दर्ज की है, जललल कथलल रूप से युवालुु कु कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गरललर कलल गया था ।

- NIA ने दो लूलुु पर भारतीय दंड संहलल की वभलनल धाराुु और **गैरकानूनी गतवलधल रोकथाम अधनललम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967** के तहत आरोप लगाए हैं ।

नोट: **कट्टरता** वह प्रकरलल है जसलके द्वारा एक वयकतलल समूह **चरम वशलवासुु और वचलरधाराुु कु अपनाता** है जो मुख्यधारा के **समाज के मूल्युु, मानदंडुु एवं कानूनुु कु असवीकार या वशलध करते हैं** । इसमें प्राल: प्रचार, प्रेरक बयानबाज़ी तथा प्रेरक वयकतललल या समूहुु का जोखमल शामिल होता है जो चरमपंथी वचलरुु व वचलरधाराुु कु बढ़ावा देते हैं ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:

- **परचलल:**
 - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसल है जो **आतंकवाद, उग्रवाद** और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलुु से संबंधलत अपराधुु की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़मलमेदार है ।
 - कसलल देश में संघीय एजेंसललुु के पास वशलष रूप से उन मामलुु पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश कु प्रभावलत करते हैं, न कल केवल अलग-अलग राज्युु या प्रान्तुु से संबंधलत होते हैं ।
 - **वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलुु** के बाद **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008** के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचाललत होती है ।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधनललम, 2008 में बदलाव करते हुए **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधनललम, 2019** कु जुलाई 2019 में पारलत कलल गया था ।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलसल बलुु और अन्य एजेंसललुु से प्राप्त आतंकवाद से संबंधलत मामलुु की जाँच करने की शकतल है । इसके पास **राज्य सरकारुु से पूर्व अनुमतल/प्राप्त कलल बना राज्य की सीमाुु के मामलुु की जाँच करने का भी अधिकार है** ।
- **कार्य:**
 - आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलुु से संबंधलत **खुफलल सूचनाुु का संग्रह, वशल्लेषण और प्रसार करना** ।
 - **आतंकवाद** और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधलत मामलुु में भारत एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसललुु के साथ समन्वय करना ।
 - **कानून प्रवर्तन एजेंसललुु और अन्य हतलधारकुु के ललल क्षमता नरलमाण कार्यक्रम आयोजलत करना** ।
- **जाँच क्षेत्र:**
 - NIA के जाँच के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं । NIA अधनललम, 2008 की धारा 6 के तहत **राज्य सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जाँच के ललल केंद्र सरकार कु सूचीबद्ध अपराधुु से संबंधलत मामलुु का उललेख कर सकती है** ।

- केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा वदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को **केंद्र सरकार की मंजूरी** लेनी होती है।
- **वामपंथी उग्रवाद (LWE)** के आतंकी वतितपोषण से संबंधित मामलों से नपिटने के लिये एक विशेष प्रकोषट है। किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है। अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समकष प्रस्तुत कया जाता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (संशोधन) अधनियिम, 2019 के तहत कयि गए परविरतन:

- **भारत के बाहर अपराध:**
 - NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जाँच करने की शकती थी, लेकनि संशोधति अधनियिमम्वइसे **भारत के बाहर कयि गए अपराधों की जाँच करने** की अनुमति देता है, जब तक कयिह **अंतरराष्ट्रीय संधयिों और शामिल देशों के कानूनों का पालन** करता है।
 - केंद्र सरकार का मानना है कअगर कोई अपराध भारत के बाहर कया गया है, लेकनि **अधनियिम के अधकिार कषेत्र** में आता है, तो वह NIA को मामले की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- **कानून का वसित्तुत दायरा:**
 - **NIA अधनियिम की अनुसूची** में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच NIA कर सकती है।
 - अनुसूची में मूल रूप से **परमाणु ऊर्जा अधनियिम, 1962**, गैरकानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम, 1967 और अपहरण-रोधी अधनियिम, 1982 जैसे अधनियिम शामिल थे।
 - संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधित मामलों की भी जाँच कर सकती है:
 - **मानव तसकरी**
 - **नकली मुद्रा या बैंक नोट**
 - नषिदिध हथयार
 - **साइबर आतंकवाद**
 - वसिफोटक पदारथ अधनियिम, 1908 के तहत अपराध
- **वशिष न्यायालय:**
 - अधनियिम, 2008 ने **अधनियिम के तहत** मामलों की सुनवाई के लिये वशिष न्यायालयों की स्थापना की।
 - वर्ष 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को **अधनियिम के तहत सूचीबद्ध अपराधों** की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति करने की अनुमति देता है।
 - ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामरश करना होगा। यदएक कषेत्र में कई वशिष न्यायालय मौजूद हैं, तो **मामले को सबसे वरषिठ न्यायाधीश द्वारा साँपा जाएगा**।
 - राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति कर सकती हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधनियिम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची नरिदषिट करती है जनिकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामिल हैं:
 - **वसिफोटक पदारथ अधनियिम**
 - **परमाणु ऊर्जा अधनियिम**
 - **गैर-कानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम**
 - **अपहरण वरिधी अधनियिम**
 - **नागरकि उड्डयन अधनियिम की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी अधनियिमों का दमन**
 - **सारक अभसिमय (आतंकवाद का दमन) अधनियिम**
 - **महाद्वीपीय शेलफ अधनियिम पर समुद्री नेवगिशन और नशिचति प्लेटफॉर्मों की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन**
 - **सामूहकि वनिाश के हथयार और उनकी आपूरता पिरणाली (गैर-कानूनी गतविधियिों नषिध) अधनियिम**
 - **भारतीय दंड संहति, शसत्र अधनियिम और सूचना परौदयोगकि अधनियिम के तहत कोई अन्य परासंगकि अपराध।**
 - **नारकोटक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपकि सबसटेंस एकट**

स्रोत: इंडयिन एकसपरेस